

खबर संक्षेप

बरसात में बरते विद्युत सुरक्षा, पोल-ट्रांसफार्मर और तारों से रखें सुरक्षित दूरी



शहडोल। बारिश के मौसम में तेज आंधी, तूफान और लगातार वर्षा के कारण विद्युत दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसे देखते हुए विद्युत विभाग ने जिलेवासियों से विशेष सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग जितेंद्र गुप्ता ने नागरिकों से कहा है कि विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर तथा हाईटेंशन एवं प्लगटॉ विद्युत लाइनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। साथ ही अपने पालतू पशुओं को बिजली के खंभों या तारों से न बांधें। बारिश के दौरान गीले हाथों अथवा नंगे पैर किसी भी विद्युत उपकरण, तार या स्विच बॉर्ड को छूने से बचें। उन्होंने बताया कि जलमय वाले स्थानों पर बिजली के खंभों के पास जाना खतरनाक हो सकता है। ऐसे स्थानों पर रखे विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। घरों की पुरानी या खराब वायरिंग, ढीले कनेक्शन, पानी का रिसाव और कमजोर अर्थिंग भी करंट फैलने का कारण बन सकते हैं। इसलिए समय-समय पर प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन से घरेलू वायरिंग और अर्थिंग की जांच अवश्य करानी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कटे-फटे विद्युत तारों को तुरंत बदलें और केवल आईएसआई मार्क वाले विद्युत उपकरण एवं तारों का ही उपयोग करें। घरों में मिनिस्चर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) और उचित अर्थिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि कहीं बिजली का तार, केबल या पोल टूटा हुआ दिखाई दे तो उसके पास न जाएं और न ही उसे छूने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। किसी भी विद्युत आपात स्थिति, दुर्घटना की आशंका अथवा टूटे हुए तार की सूचना तत्काल विद्युत विभाग को दें। विद्युत संबंधी शिकायत या आपात स्थिति में उम्मीदवार टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। अथवा अपने निकटतम विद्युत वितरण केंद्र में सूचना दे सकते हैं।

नौसमी बीमारियों से रहे सतर्क एवं जागरूक: सीएमएचओ

शहडोल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने जिले के नागरिकों से वर्षाऋतु में होने वाली बीमारियों के बचाव संबंधित अपील करते हुए कहा कि वर्षाऋतु के दौरान शहडोल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उष्ण, दस्त, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, सर्दी, जुकाम सहित अन्य संक्रामक बीमारियों के मामले बढ़ने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि वर्षाऋतु में होने वाली बीमारियों से आमजन को जागरूक एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि भोजन करने से पहले तथा शीत के बाद साबुन और स्वच्छ पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं, छेनासा ताजा एवं गर्म भोजन का सेवन करें, भोजन और पेयजल को ढककर रखें। केवल स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी का उपयोग करें, अपने घर और आसपास साफ-सफाई रखें। उन्होंने कहा कि अस्वस्थ होने पर त्वरित चिकित्सकीय परामर्श ले जिससे बीमारी का समुचित उपचार किया जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने जिलेवासियों से विशेष सावधानी बरतने तथा बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने की अपील की है।

सीएमएचओ ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवलौद एवं परियोजना चिकित्सालय का निरीक्षण

शहडोल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. राजेश मिश्रा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवलौद एवं परियोजना चिकित्सालय का औपक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, दवा वितरण, साफ-सफाई, मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं तथा आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएमएचओ डॉ. मिश्रा ने अस्पताल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अस्पताल में पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने तथा आवश्यक सुधारत्मक कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। <

शहडोल नगर पालिका का जहरीला खेल नलों से टपक रहा गंदा पानी, सड़कों पर गड़ों का राज

सो रहे साहब और लापता हैं जनप्रतिनिधि शहडोल।

जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद इन दिनों विकास के दावों के नाम पर जनता के सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रही है। शहर की सरकार इस कदर संवेदनहीन हो चुकी है कि उसे न तो सड़कों पर तड़पती जनता की परवाह है और न ही घरों में पहुंच रहे धीमे जहर की। जी हां, इन दिनों शहडोल नगर पालिका द्वारा शहर के घरों में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, वह पीने लायक तो दूर, हाथ धोने के काबिल भी नहीं है। नलों से मटमैला, बदबूदार और गंदा पानी टपक रहा है, लेकिन इस गंभीर लापरवाही पर न तो नगर पालिका के प्रशासनिक अफसरों के कान पर जूं रेंग रही है और न ही जनता के वोटों पर ऐश करने वाले माननीय पार्षदों को इसकी कोई चिंता है।

बीमारियां बांट रही है नगर पालिका

शहर के विभिन्न वार्डों से आ रही तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। सुबह जब लोग पीने के पानी के लिए नल खोलते हैं, तो उसमें साफ जल के बजाय क्रीचड्युक्त और दूषित पानी की धार निकलती है। हद तो यह है कि इस पानी की शुद्धता की जांच करने या वाटर फिल्टर प्लांट की देख-रेख करने वाला कोई जिम्मेदार



नपा में मौजूद नहीं है। अंचल की जनता आक्रोशित होकर पूछ रही है कि इस दूषित पानी को पीने से यदि शहर में कोई महामारी फैलती है या किसी मासूम की जान जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तब एसी कमरों में बैठने वाले नपा के अधिकारी और अपनी राजनीति चमकाने वाले नेता इसकी जिम्मेदारी लेंगे? जनता

को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर करना आखिर शहडोल नपा का कैसा सद्भाव है?

सडकों की हालत बयां कर रही पार्षदों का वाई प्रेम

शहर की सडकों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। मुख्य मागों

शहडोल संभाग को मिली संजीवनी: आदित्य सुपर स्पेशलिटी की 5वीं वर्षगांठ पर अत्याधुनिक कैथलैब का ऐतिहासिक शुभारंभ



शहडोल। विंध्य अंचल और विशेषकर शहडोल संभाग के स्वास्थ्य इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण सालों से रेफर कल्चर का दर्श झेल रहे इस जनजातीय बाहुल्य इलाके को अब दिल की बीमारियों के इलाज के लिए बड़े महानगरों की ओर नहीं दौड़ना पड़ेगा। क्षेत्र के प्रतिष्ठित और भरोसेमंद चिकित्सा संस्थान आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपनी सफलता के शानदार 5 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक उपलक्ष्य में अंचलवासियों को हृदय रोग के संतुलन उपचार और त्वरित सेवा के लिए अत्यंत अत्याधुनिक कैथलैब की अनुपम सौगात दी है। गौरतलब है कि शहडोल संभाग में हृदय जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों के आपातकाल (इमरजेंसी) के समय स्थानीय स्तर पर कोई पुख्ता व्यवस्था न होने से मरीजों और उनके परिजनों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। जबलपुर, नागपुर या बिलासपुर ले जाते समय रास्ते में ही गोल्डन ऑवर (हार्ट अटैक के बाद का शुरुआती कीमती समय) बीत जाने के कारण न जाने कितने लोग असमय ही काल के गाल में समा चुके हैं। आदित्य हॉस्पिटल का यह कदम इस अंचल के लिए एक जीवनदायिनी मौल का पत्थर साबित होगा।

संभाग की सबसे बड़ी जरूरत हुई पूरी: सांसद

अस्पताल के पंचम स्थापना दिवस के इस गौरवशाली और भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहडोल संभाग की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह उपस्थित रहीं। उन्होंने फीता काटकर अत्याधुनिक कैथलैब का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसमुदाय को संबोधित करते हुए सांसद हिमाद्री सिंह ने कहा एक सर्वसुविधाजनक कैथलैब और कुशल हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम शहडोल संभाग की बरसों पुरानी और सबसे बुनियादी जरूरत थी, जिसे आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक अनमोल सौगात के रूप में धरातल पर उतारा है। निश्चित रूप से आपातकालीन स्थितियों से लेकर सामान्य हृदय रोगियों के लिए भी यह उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह अस्पताल भविष्य में भी हर परिस्थिति में अंचल की जनता की निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के सेवा और समर्पण को सलाम: जयसिंह

समारोह के विशिष्ट अतिथि जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक जयसिंह मरावी ने अस्पताल के डॉक्टरों की टीम की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के बड़े-बड़े महानगरों और नामचीन संस्थानों को छोड़कर जो विशेषज्ञ चिकित्सक आज इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पूरे समर्पण और आत्मीयता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे वंदनीय हैं। उन्होंने सभी चिकित्सकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद

जताई कि वे इसी तमयता के साथ अंचल के गरीब और जरूरतमंद मरीजों का इलाज करते रहेंगे।

अंचल का विश्वास जीतना ही हमारा मूल मकसद: डॉ. आदित्य द्विवेदी

एक बेहद भावुक और संकल्प से भरे उद्बोधन में आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दूरदर्शी संचालक डॉ. आदित्य द्विवेदी ने अपनी भावी स्वास्थ्य योजनाओं का खाका खींचा। उन्होंने अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए और भविष्य की तैयारियों को रेखांकित करते हुए कह स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में शहडोल संभाग को सर्वसुविधा युक्त बनाना और यहां के मरीजों को रेफर कल्चर की प्रताड़ना से शत-प्रतिशत मुक्ति दिलाना ही हमारी स्थापना का मूल ध्येय रहा है। आज 5 साल पूरे होने पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चिकित्सा के क्षेत्र में महानगरों की तर्ज पर आदित्य परिवार आने वाले समय में इससे भी बेहतर सुविधाएं और विश्वस्तरीय उपचार की व्यवस्था यहीं शहडोल की माटी पर करने के लिए प्रतिबद्ध है। बस, अंचल की आवाम को हमारे ऊपर इसी तरह विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि उनका यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत बने और हम उनकी हर उम्मीद पर खरे उतर सकें। इस गरिमामयी कार्यक्रम में डॉ. आदित्य द्विवेदी के पिता ललन राम द्विवेदी की गरिमापूर्ण उपस्थिति ने पूरे माहौल को और अधिक आत्मीय, संस्कारवान और ऊर्जास्वित बना दिया।

वरिष्ठ चिकित्सकों, समाजसेवियों और डिजिटल हीरोज का हुआ सम्मान

आदित्य परिवार ने अपने इस उत्सव को केवल अपनी सफलता तक सीमित न रखते हुए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने वाले नायकों के सम्मान से जोड़कर इसे और अधिक दिल्य बना दिया। मुख्य अतिथियों और अस्पताल प्रबंधन के कर-कमलों से अंचल की प्रख्यात विभूतियों का भव्य सम्मान किया गया। वरिष्ठ चिकित्सक सम्मान (चिकित्सा क्षेत्र के स्तंभ): अंचल में दशकों से चिकित्सा सेवा की मिसाल पेश करने वाले नगर के प्रतिष्ठित

वरिष्ठ डॉक्टरों डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, डॉ. अशोक जैन, डॉ. एन.के. सोनी, डॉ. उमेश नामदेव, डॉ. राजेश मिश्रा, डॉ. अलका तिवारी, डॉ. जी.डी. सिंह, डॉ. एस.पी. राय, डॉ. एस.एन. दुबे, डॉ. सुधा नामदेव एवं डॉ. एस.सी. त्रिपाठी का शाल-श्रीफल और स्मृति चिह्न भेंटकर भावभीना नागरिक अभिनंदन किया गया। समाजसेवी सम्मान: निःस्वार्थ भाव से समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अग्रणियों— सिखर चंद, रूपाली सिंघई और गौरव मिश्रा को मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। डिजिटल इंप्लुएंसर सम्मान: सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में रचनात्मकता, जन-जागरूकता और सकारात्मक संदेश प्रसारित करने वाले युवा पीढ़ी

के होनहारों अमित गर्ग, संजीत सोनी, प्रशांत मिश्रा, ऋषभ साह और पुष्कर साहू को भी उनकी सराहनीय भूमिका के लिए मंच से विशेष रूप से नवाजा गया। इस पूरे भव्य और गरिमामयी आयोजन का अत्यंत कुशल, जीवंत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला संचालन सुप्रसिद्ध एंकर सौम्या सिंघई, अनिल द्विवेदी एवं श्री जसपाल जी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य समारोह के समापन के पश्चात, उपस्थित अतिथियों के लिए आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परिवार द्वारा एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सुरुचिपूर्ण रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जहां सभी ने मधुर स्मृतियों के साथ विदाई ली और अस्पताल के सुनहरे भविष्य की कामना की।

हरिभूमि

समाचार ही नहीं, विचार भी

सुनहरा मौका, सुनिश्चित उपहार 2026

प्रथम उपहार 1 कार

द्वितीय उपहार 3 नग वाईक

तृतीय उपहार 10 नग LED TV

चतुर्थ उपहार 5 नग फ्रीज

पांचवा उपहार 8 नग वाशिंग मशीन

छठवां उपहार 15 नग गैस चूल्हा

सातवां उपहार 25 नग सिलिंग फैन

आठवां उपहार 40 नग ट्राली बैग

नवां उपहार 500 नग हॉट पॉट

दसवां उपहार 600 नग लंच बाक्स

ग्यारहवां उपहार प्रत्येक प्रतिभागी को सात्वता उपहार

नियम एवं शर्तें :-

✦ यह सुनहरा मौका, सुनिश्चित उपहार योजना 1 मई 2026 से 31 दिसम्बर 2026 की अवधि के लिए है।

✦ हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक इसमें भाग ले सकते हैं।

✦ महालक्ष्मी हार में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को एक सुनिश्चित उपहार जीतने का अवसर होगा।

✦ इस योजना अवधि में हरिभूमि समाचार पत्र में कुल 50 कूपन (35 साप्ताह्य कूपन एवं 15 मासिक कूपन) प्रकाशित किये जाएंगे।

✦ योजना में भाग लेने के लिये पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित कार्ड पर उपरोक्त अवधि के दौरान समाचार पत्र में प्रकाशित 50 कूपनों में से कुल 30 कूपन (20 साप्ताह्य एवं 10 मासिक कूपन) क्लिप्प करने होंगे।

✦ कोटेडोथि का कट-कट कूपन व कार्ड कट मान्य नहीं होंगे।

✦ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सभी नियम लागू होंगे।

✦ सुनहरा मौका सुनिश्चित उपहार योजना के विजेता को आवक के नियम व शर्त मान्य होगी।

✦ हरिभूमि निर्माणांक महसू का निर्माण अवधि एवं सर्वमान्य होगा।

✦ किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र राखुर (छ.न.) होगा।

✦ विषय में दर्राई नष्ट उपहार वार्षिक उपहार से भिन्न हो सकते हैं।

✦ हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हो सकते।

आज ही हरिभूमि की प्रति बुकिंग करावें

हरिभूमि कार्यालय : 66/1, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई जिला जबलपुर
मो. 9479623424, 9340637789



खबर संक्षेप

रपटे-पुलिया पार करने की मूल न कटें:

कलेक्टर हर्षल पंचोली

अनूपपुर। जिले में लगातार सक्रिय मानसून और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए क ले क ट र हर्षल पंचोली ने जिलेवासियों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा सलाह जारी की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रपटे, पुल-पुलिया या सड़क पर यदि बाढ़ का पानी बह रहा हो तो उसे पार करने का प्रयास बिल्कुल न करें। थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

कानून के शिकंजे में चीतल को केला खिलाने वाला रीलबाज



उमरिया। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से वन्यजीवों की सुरक्षा और नियमों को ताक पर रखने वाले तथ्यांकित पर्यटकों के लिए एक बड़ी और सबक सिखाने वाली खबर सामने आई है। मगधी गेट के सामने वन्यजीव (चीतल) को केला खिलाकर सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने का स्टंट करने वाले एक रीलबाज को बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए प्रबंधन ने आरोपी को दबोचकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत सीधे न्यायालय के कटघरे में खड़ा कर दिया है।

मामला तब खुला जब यह महाशय मगधी गेट के पास एक चीतल को केला परोस रहे थे। उसी समय पंचपेढ़ी पर्यटन जोन से सफारी कर लौट रहे एक जागरूक पर्यटक ने इस गैर-कानूनी हरकत को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन की नौद टूटी। अधिकारियों ने तत्काल तकनीकी जांच बिठाई, आरोपी का चेहरा और गाड़ी ट्रैस की और उसे दबोच लिया।

पार्क प्रबंधन ने इस कार्रवाई के जरिए साफ संदेश दिया है कि राष्ट्रीय उद्यान कोई चिड़ियाघर नहीं है, जहां आप जानवरों को अपनी मर्जी से कुछ भी परोस दें। बाहरी और अप्राकृतिक खाना खिलाने से वन्यजीवों का स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, साथ ही वे आत्मनिर्भर शिकार या भोजन तलाशने की अपनी प्राकृतिक आदत खो देते हैं। वे इंसानों पर निर्भर होकर भिखारी बनने लगते हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने इस सख्त एक्शन के बाद सभी सैलानियों और स्थानीय लोगों को आर्म चेतावनी जारी की है। प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि सफारी के दौरान वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यदि भविष्य में कोई भी रील बनाने, फोटो खिंचने या शौक के चक्कर में वन्यजीवों को खाना खिलाने या उनके प्राकृतिक आवास में खलल डालते पाया गया, तो उसका अगला ठिकाना सीधे जेल की कोठरी होगी।

यूनिवर्सिटी की लेटलतीफी: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खोला मोर्चा!



शहडोल। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय एक बार फिर अपनी अकर्मण्यता और लचर व्यवस्था के कारण विवादों के घेरे में है। विश्वविद्यालय प्रशासन की भारी लापरवाही का खमियाजा अब सीधे तौर पर हजारों सीधे-साधे छात्रों को अपने भविष्य की बर्बादी के रूप में झुगतना पड़ रहा है। इस गंभीर संकट को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संगठन के जिला संयोजक अमन त्रिपाठी के नेतृत्व में कुलसचिव के नाम एक तीखा झांपन सौंपकर विश्वविद्यालय के सुस्त रवैए पर जोरदार हमला बोला गया है।

4 महीने की प्रशासनिक नींद और छात्रों का पूरा साल बर्बाद!

मामला यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षा और प्रथम वर्ष की पूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षा से जुड़ा है। विश्वविद्यालय को नियमानुसार प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा आज से ठीक 4 महीने पहले ही संपन्न करा लेनी चाहिए थी, ताकि छात्र समय पर अपना परिणाम देखकर आगे की रणनीति बना सकें। लेकिन, जिम्मेदार अधिकारी महीनों तक कुंठकर्णी नौद सोते रहे। अब जब पाजी सिर से ऊपर जा चुका है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए

बुढ़ार में आकाशीय बिजली का कहर: थाने के कंप्यूटर और सर्वर जलकर खाक, 3 दिनों से ऑनलाइन कामकाज ठप



बुढ़ार। नगर में पिछले शनिवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली का कहर आम जनजीवन के साथ-साथ शासकीय कार्यालयों पर भी भारी पड़ रहा है। पिछले दिनों बुढ़ार थाने के समीप स्थित यूकेलिप्टस के पेड़ पर अचानक गाज (आकाशीय बिजली) गिर गई। यह हादसा इतना भयानक था कि थाना परिसर में द्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मों बाल-बाल बच गए, लेकिन थाने के डिजिटल सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है।

लाखों के उपकरण खाक, फरियादी परेशान

बिजली गिरने के जोरदार झटके से बुढ़ार थाने का पूरा डिजिटल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। हादसे के



वक्त पुलिसकर्मों 5 कंप्यूटरों पर काम कर रहे थे। गाज गिरते ही हार्ड वोल्टेज के कारण थाने के: सीसीटीएनएस (CCTNS) सिस्टम,सर्वर सिस्टम और डेस्कटॉप मॉनीटर,सीपीयू (CPU) एवं अन्य तकनीकी उपकरण पुरी तरह जलकर खाक हो गए।

संवाद और रिपोर्टिंग पूरी तरह ठप:

पिछले तीन दिनों से थाने का मुख्य सर्वर बंद पड़ा है। इसके चलते थाने का बाहरी संवाद और

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एकलव्य विद्यालय पाली में राष्ट्रवाद एवं युवा पंजीकरण अभियान का मत्स्य आयोजन

बिरसिंहपुर पाली। महान राष्ट्रवादी विचारक, शिक्षाविद् एवं अखंड भारत के स्वप्नदृष्टा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म-जयंती के अवसर पर सोमवार को पाली ब्लॉक स्थित एकलव्य विद्यालय में एक गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत माय युवा भारत माय भारत के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करना था।

न्यायाधीश तारा मार्को ने दिया मार्गदर्शन, माय भारत से जुड़ने का आह्वान

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यवहार न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री तारा मार्को एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माय युवा



दैनिक रिपोर्टिंग का काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी दूर-दूर से आने वाले फरियादियों को हो रही है, क्योंकि सर्वर न होने से उनकी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज नहीं हो पा रही हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई सूचना

थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार के द्वारा इस बड़े तकनीकी नुकसान और व्यवस्था ठप होने की पूरी जानकारी जिला मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है। जल्द से जल्द नए उपकरण लगाने और सर्वर को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम जनता को हो रही परेशानी को दूर किया जा सके और पुलिसिंग व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट सके।

चूल्हे से कॉलेज तक: कुमरूदु की बहू ने एमपीपीएससी में रचा इतिहास

पाली की आदिवासी बेटी प्रियंका सिंह मसराम सहायक प्राध्यापक बनीं, पेसा क्षेत्र को मिली नई पहचान

उमरिया। आदिवासी महिला की जगह सिर्फ रसोई में है, इस पुरानी सोच को ग्राम कुमरूदु की बहू श्रीमती प्रियंका सिंह मसराम ने अपने हौसले से तोड़ दिया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एम पी पी एस सी द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक हिन्दी परीक्षा में चयनित होकर उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे उमरिया जिले का नाम रोशन किया है।

पेसा क्षेत्र से शिक्षा की उड़ान

पाली विकासखंड प्रदेश के उन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आता है जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है और पेसा अधिनियम 1996 प्रभावी है। यहां शिक्षा की पहुंच आज भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रियंका की यह सफलता सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि पूरे अंचल के लिए सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गई है।

संघर्ष से सफलता तक

प्रियंका की कहानी हर गांव की बेटी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि अगर अवसर, शिक्षा और

अटूट संकल्प साथ हों, तो आदिवासी अंचल की बहुएं-बेटियां भी देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में बाजी मार सकती हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे ग्राम कुमरूदु और पाली विकासखंड में खुशी की लहर है।



दो अफसर, एक प्रेरणा

उल्लेखनीय है कि प्रियंका के पति श्री धर्मपाल सिंह मसराम वर्तमान में जनपद पंचायत मुलताई, जिला बैतूल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO के पद पर कार्यरत हैं। पति-पत्नी दोनों का शासन-प्रशासन में होना आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय है।समाजजनों और शुभचिंतकों ने इस सफलता को आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की नई मिसाल बताया है।

नया संदेश: कुमरूदु की इस बहू ने दिखा दिया कि अब आदिवासी महिलाएं सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं। वे अब व्याख्यान मंच से प्रदेश की नई पीढ़ी का भविष्य गाढ़ेंगी।



भारत के जिला अधिकारी श्री उमा शंकर त्रिवेदी उपस्थित रहे। अतिथियों ने माँ सरस्वती एवं डॉ. मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्य अतिथि सुश्री तारा मार्को ने अपने न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री तारा मार्को एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माय युवा

आदर्श उदाहरण है। युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझना होगा। तभी हम समाज में न्याय और समानता स्थापित कर सकेंगे। आप सभी एक जिम्मेदार नागरिक बनें।जिला अधिकारी श्री उमा शंकर त्रिवेदी ने 'माय युवा भारत' मंच की जानकारी देते हुए 'सुघन पंजीकरण अभियान' पर विशेष जोर

उमरिया जिले के सहकारिता विभाग में नियमों की उड़ रहीं धज्जियां

गृह जिले में वर्षों से पदस्थ प्रभारी अमय सिंह पर एआरसीएस पर उठे सवाल, प्रशासनिक चुप्पी से बड़ी चर्चाएं

उमरिया। मध्यप्रदेश शासन की सुशासन और पारदर्शिता की नीति के बीच जिले के सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विभाग में प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटी अमय सिंह की लंबे समय से पदस्थापना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है। आरोप है कि वे वर्षों से अपने गृह जिले उमरिया में पदस्थ हैं, जबकि शासन की स्थानांतरण नीति में निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि यदि कोई अधिकारी लंबे समय तक एक ही जिले में पदस्थ रहता है, विशेषकर अपने गृह जिले में, तो निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसी कारण सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति में ऐसे मामलों को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। लंबे समय से एक ही जिले में पदस्थापना पर सवाल स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभारी एआरसीएस अमय सिंह कई वर्षों से जिले में पदस्थ हैं। यदि यह तथ्य अमिलेखों से पुष्ट होता है, तो यह जांच का विषय बन सकता है कि उनकी पदस्थापना शासन की प्रचलित नीति के अनुरूप है या नहीं। इस संबंध में विभागीय स्तर पर अब तक कोई स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं

मामले को लेकर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि पदस्थापना नियमों के अनुरूप नहीं है, तो जिला प्रशासन अथवा संबंधित विभाग द्वारा अब तक आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट स्थिति सामने न आने से चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। सहकारिता विभाग किसानों और सहकारी समितियों से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में यदि विभाग में पदस्थ अधिकारियों की नियुक्ति या पदस्थापना को लेकर सवाल उठते हैं, तो उसका प्रभाव विभाग की कार्यप्रणाली और जनता के विश्वास पर भी पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

जांच और पारदर्शिता की मांग

जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं जागरूक नागरिकों द्वारा शासन से मांग की जा रही है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित अधिकारी की पदस्थापना शासन की नीति के अनुरूप है या नहीं। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब निगाहें शासन और वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हैं। यदि मामले में उठ रहे सवाल तथ्यात्मक रूप से सही पाए जाते हैं, तो संबंधित प्रकरण की जांच कर आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लिया जाना शासन की पारदर्शी व्यवस्था की कसौटी माना जाएगा।

पात्रता मानदंडों को थोपना प्राकृतिक न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। यदि इन शिक्षकों के भविष्य को अधर में लटकाना गया, तो इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता चरमरा जाएगी और शिक्षकों का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा।

संसद से हस्तक्षेप और ठोस कानून बनाने की मांग

शिक्षक संघ ने दैतूक शब्दों में कहा है कि न्यायपालिका केवल कानूनों की व्याख्या करती है, परंतु जनहित में आवश्यक नीतिगत और विधायी समाधान उपलब्ध कराना देश की संप्रभु संसद और निर्वाचित सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। संगठन के जिला अध्यक्ष और जिला सचिव ने संयुक्त रूप से पांच प्रमुख मांगें सामने रखी हैं कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से पूर्णतः मुक्त कर स्थायी संरक्षण दिया जाए। ऐसे शिक्षकों की सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सभी अर्जित लाभों की पूर्ण रक्षा की जाए। संसद में आवश्यक विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाकर इस वर्ग को स्थायी राहत प्रदान की जाए। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें इस विषय पर व्यापक असमंजस और डर के माहौल को समाप्त करने के लिए तत्काल स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें। शिक्षक संघ का कहना है कि यदि इस दिशा में शीघ्र ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो राष्ट्र निर्माताओं का यह आक्रोश आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।

लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट की तलवार

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा प्रधानमंत्री से विधायी संरक्षण की मांग!

शहडोल। देश के लाखों शिक्षकों के अधिकारों, वरिष्ठता और आजीविका पर एक बार फिर गंभीर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2010 में जारी की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय के बाद देश भर के शिक्षकों में भारी चिंता, मानसिक पीड़ा और असुरक्षा की भावना फैल गई है। इस गंभीर विषय को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे देश के मुखिया और संसद के हस्तक्षेप की मांग कर दी है। संगठन के पदाधिकारियों ने शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित एक अत्यंत तीखा और न्यायसंगत मांग पत्र सौंपा है।

वया दशकों की सेवा का कोई मूल्य नहीं?

इस पूरे विवाद की जड़ 23 अगस्त 2010 की वह अधिसूचना है, जिसके तहत शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा को अनिवार्य अर्हता घोषित किया गया था। इस नियम के आने से पूर्व देश के विभिन्न राज्यों में लाखों शिक्षक तत्कालीन वैध नियमों, योग्यताओं और पूरी तरह से पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से शासकीय सेवा में नियुक्त हो चुके थे। इन गुरुजनों ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष राष्ट्र निर्माण, नौनिहालों को

नियमों की घुट्टी पिला रहा है। छात्रों को फरमान सुनाना जा रहा है कि जब तक वे प्रथम वर्ष उत्तीर्ण नहीं कर लेते, तब तक उन्हें द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और उन्हें अगले साल परीक्षा देनी होगी।

फीस डूबी और भविष्य अंधकार में, कौन लेगा जिम्मेदारी?

विश्वविद्यालय के इस तानाशाही और बेतुके फैसले से छात्रों का पूरा एक साल सीधे-सीधे बर्बाद होने की कगार पर है। सवाल यह उठता है कि विश्वविद्यालय की इस अक्षमता के कारण छात्रों की जो द्यूखीन फीस और परीक्षा फीस डूब रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या कुलपति और कुलसचिव महोदय अपनी जेब से इन गरीब और मध्यमवर्गीय माता-पिता की गाढ़ी कमाई वापस करेंगे? एबीवीपी ने दैतूक शब्दों में मांग की है कि या तो छात्रों को प्रथम वर्ष से प्रमोट करके हुए उनके द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म तुरंत स्वीकार किए जाएं या फिर एक बीच का रास्ता निकाला जाए। यदि कोई छात्र आगे चलकर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसे अंतिम वर्ष में प्रवेश के पात्र न माना जाए। इससे छात्रों का साल और फीस दोनों सुरक्षित रहेंगे।

तारीख बढ़ाने और न्याय की मांग

छात्र संगठन ने अल्टीमेटम दिया है कि छात्रों के भविष्य और उनके परिजनों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया तत्काल बिना किसी रुकावट के पराम की जाए और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में भी सम्मानजनक वृद्धि की जाए।



खबर संक्षेप

3.83 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, 78 हजार रुपये की खेप जब्त



अनूपपुर। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3.83 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 78 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ उसे कहाँ से मिला और इसका नेटवर्क किन-किन लोगों तक फैला हुआ है। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त मुराब (आईपीएस) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम एवं एसडीओपी नवीन तिवारी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार रात थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद जैन के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई की। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने पॉलीटेक्निक कॉलेज रोड क्षेत्र में घेराबंदी कर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। विधिवत तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 3.83 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिव तिवारी उर्फ शिवम (20 वर्ष), पिता शिवशंकर तिवारी, निवासी वार्ड क्रमांक-2, नई सब्जी मंडी, पटौराटोला, अनूपपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी से यह पता लगाने में जुटी है कि ब्राउन शुगर की खेप कहाँ से लाई गई थी, इसे किसे सप्लाई किया जाना था और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन हैं। मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शिव तिवारी के विरुद्ध पूर्व से भी विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के तहत समीक्षा बैठक 8 जुलाई को
कटनी। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी विकासखंड योजना में चयनित रीटी विकासखंड में विभिन्न संकेतकों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक जिला पंचायत के सभा कक्ष में बुधवार, 8 जुलाई को जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रती कौर से की अध्यक्षता में 11 जनों से आयोजित की गई है। जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, किसान कल्याण तथा कृषि, भूमि संरक्षण, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं पशु चिकित्सा विभाग के जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को संकेतकों को संतुष्ट करने हेतु निर्धारित एजेंडा के अनुसार विंडो 2.0 इनोवेटिव प्रोजेक्ट अंतर्गत अंतर्गत डीपीआर तैयार कर विभाग से संबंधित बिंदुवार अद्यतन प्रगति की जानकारी सहित निर्धारित समय एवं स्थान पर अधिकारियों को उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए हैं।

स्थानांतरण आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक, शिक्षकों को मिली बड़ी राहत



अनूपपुर। स्थानांतरण आदेशों को चुनौती देने वाले शिक्षकों को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने सुनवाई के दौरान दो शिक्षकों के स्थानांतरण आदेशों पर अंतरिम रोक (स्टे) लगा दी है। जानकारी के अनुसार, अनूपपुर जिले के विद्या निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल, बदरा कालरी में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक शिवनारायण शर्मा (गणित) का स्थानांतरण शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, देवगवा कर दिया गया था। स्थानांतरण आदेश निरस्त कराने के लिए उन्होंने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अनूपपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई को स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय के इस आदेश से शिक्षक को फिलहाल अपने वर्तमान पदस्थान पर कार्य करने की राहत मिल गई है। इसी प्रकार गोपाल नारायण श्रीवास्तव, जिनका स्थानांतरण शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय, रवा से शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, कमवा, विकासखंड कुसुमी, जिला सीधी किया गया था, उन्हें भी उच्च न्यायालय से राहत मिली है। न्यायालय ने उनके स्थानांतरण आदेश पर भी अंतरिम स्टे प्रदान किया है। शिक्षकों का कहना है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में नियमों और निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायालय द्वारा दोनों मामलों में अंतरिम राहत दिए जाने के बाद ऐसे अन्य शिक्षक भी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जो स्थानांतरण आदेशों से असंतुष्ट हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश को प्रदेश में चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अब संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालय की आगामी सुनवाई के बाद होगा।

सूचना दबाने के आरोपों में घिरा बॉक्सइट प्रबंधन

इयूटी पर तैनात चौकीदार की आकाशीय बिजली से मौत

दूसरे दिन ग्रामीणों की सूचना पर हरकत में आया प्रशासन तीन साल से बंद अस्पताल और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

अनूपपुर/राजेन्द्रग्राम। जिले के राजेंद्रग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित चचानडीह बॉक्साइट खदान में इयूटी के दौरान एक चौकीदार की आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत ने खदान प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद प्रबंधन पर घटना की जानकारी छिपाने, पुलिस और प्रशासन को समय पर सूचना नहीं देने तथा कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करने के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि यदि गांव के लोगों ने अगले दिन प्रशासन को सूचना नहीं दी होती, तो मामला शायद दबा दिया जाता। जानकारी के अनुसार सोन सिंह बैगा (57 वर्ष), पिता गोड़ी बैगा, निवासी ददराटोला, चचानडीह बॉक्साइट खदान में चौकीदार के रूप में कार्यरत थे। बताया जाता है कि घटना के समय वह अपनी नियमित इयूटी पर तैनात थे। इसी दौरान मौसम अचानक खराब हुआ और तेज गर्जना के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना इतनी भयावह थी कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला।

ग्रामीणों का आरोप प्रबंधन ने छिपाई घटना
हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि



खदान प्रबंधन ने पुलिस, राजस्व विभाग अथवा स्थानीय प्रशासन को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी कराने के बजाय मृतक का शव सीधे उसके घर पहुंचा दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र में इयूटी के दौरान हुई मृत्यु के मामले में यह गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि क्या नियमों का पालन किया गया या उन्हें दरकिनार कर मामले को शांत करने का प्रयास हुआ।

दूसरे दिन सरपंच की सूचना पर पहुंची पुलिस
ग्रामीणों के अनुसार घटना की जानकारी अगले दिन गांव के सरपंच तक पहुंची। इसके बाद सरपंच ने डायल-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही राजेंद्रग्राम पुलिस, चिकित्सकीय दल और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा तैयार किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक

वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की। अब पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

तीन साल से बंद पड़ा अस्पताल, मजदूरों की जान जोखिम में
इस घटना ने खदान क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान परिसर में श्रमिकों के उपचार के लिए अस्पताल का निर्माण किया गया था, लेकिन वह पिछले लगभग तीन वर्षों से बंद पड़ा है। अस्पताल बंद होने के कारण किसी भी दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार तक उपलब्ध नहीं हो पाता। मजदूरों को कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे कई बार घायल की जान पर बन आती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि करोड़ों रुपये के औद्योगिक संचालन के बीच श्रमिकों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा तक उपलब्ध क्यों नहीं है।



क्या सुरक्षा मानकों का हो रहा था पालन?
आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खदानों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा-निर्देश और आपातकालीन प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि घटना के समय मौसम खराब होने के बावजूद क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था, क्या कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के निर्देश दिए गए थे और क्या खदान प्रबंधन के पास आपदा से निपटने की कोई प्रभावी व्यवस्था मौजूद थी।

ग्रामीणों में आक्रोश, निष्पक्ष जांच की मांग
घटना के बाद ददराटोला और आसपास के गांवों में लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, घटना की सूचना छिपाने के आरोपों की जांच करने तथा दोषी पाए जाने पर



संबंधित अधिकारियों और खदान प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बंद पड़े अस्पताल को तत्काल शुरू करने, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई है।



सशक्त राष्ट्र निर्माण में हर कार्यकर्ता निभाएं अपनी भूमिका-सांसद

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आज हुआ साकार-मंत्री दिलीप जायसवाल

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला अनूपपुर के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम की अध्यक्षता में सोमवार को भाजपा कार्यालय अनूपपुर में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर विशाल कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल थे। विशिष्ट अतिथियों में शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह, जिला प्रभारी संजय साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल गुप्ता, रामदास पुरी, आधाराम वैश्य, जिला महामंत्री श्याम नारायण शुक्ला एवं सिद्धार्थ शिव सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि मंत्री दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान का विरोध करते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि डॉ.

मुखर्जी ने जिस अखंड भारत और सशक्त राष्ट्र का सपना देखा था, वह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता होने पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता वर्ष के 365 दिन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से संगठन के लिए कार्य करता है। यही कारण है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर सर्वोच्च दायित्व तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में प्रत्येक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र की मोदी सरकार एवं मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार जनहित में लगातार कार्य कर रही है। यदि किसी कार्य में समय लगता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना होगा। सम्मेलन में उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी अपने उद्बोधन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला पदाधिकारी, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री सिद्धार्थ शिव सिंह के द्वारा किया गया। उक्त जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह द्वारा प्रदान की गई।

फलदार पौधों का हो रोपण, एक सप्ताह में पूरा करें शत-प्रतिशत नामांकन

सर्पदंश व आकाशीय बिजली की घटनाओं पर रहे कड़ी निगरानी-कलेक्टर



हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले में वर्षा ऋतु के दौरान राहत, सुरक्षा और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान को जनआंदोलन का रूप देते हुए गुणवत्तायुक्त फलदार पौधों का रोपण कराया जाए तथा कक्षा 1 से 8 तक के शरा सभी बच्चों का एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर हर्षल पंचोली ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित समय-सीमा पत्रों एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान में केवल अधिकृत नर्सरियों से गुणवत्तायुक्त एवं फलदार पौधे खरीदे जाएं। पौधारोपण

के बाद उनकी सुरक्षा के लिए ट्रैट-गार्ड लगाए जाएं तथा प्रतिदिन फोटो अपलोड कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि अभियान केवल औपचारिकता न बनकर स्थायी हरियाली का माध्यम बने। बैठक में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में शरा सभी बच्चों का नामांकन अभियान चलाकर आगामी एक सप्ताह में पूरा किया जाए। समीक्षा में बताया गया कि अब तक 94.3 प्रतिशत नामांकन हो चुका है। उन्होंने आगबोझी केंद्रों से विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया तेज करने, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग के बेहतर समन्वय से कार्य करने तथा विद्यार्थियों को निरुत्थुक प्रसूतक एवं साइकिल वितरण के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्षा

ऋतु में हाथियों की बढ़ती गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि फसल, मकान, पशुधन अथवा जनहानि से प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने वन विभाग को हाथियों की गतिविधियों पर चौकसी घंटे निगरानी रखने, प्रभावित गांवों में सर्तकता बढ़ाने तथा प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो ट्रक कहा कि गुआवजा वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में वर्षा जलित आपदाओं को लेकर भी विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सर्पदंश, आकाशीय बिजली, मकान क्षति एवं पशुहानि जैसी घटनाओं की प्रतिदिन रिपोर्ट पटवारियों द्वारा की जाए तथा तहसीलदार उसकी निगमित मॉनिटरिंग

करें। वहीं जलजलित रोगों की रोकथाम के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को सभी पेयजल स्रोतों की जांच, वलौरीनिश्चय

तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

<